

Ph.D. IN PUBLIC ADMINISTRATION (PHDPA)

Term-End Examination

00693

June, 2019

**RPA-103 : CONTEMPORARY ISSUES IN
GOVERNANCE**

Time : 3 hours

Maximum Marks : 100

(Weightage : 70%)

Note : Attempt any five of the following questions in about 500 words each. All questions carry equal marks.

1. Explain the concept of New Public Management and bring out its theoretical foundations. 20
2. Examine the malnutrition issues pertaining to maternal and child health in India. 20
3. "Digital India can enable the last mile inclusiveness." Comment. 20
4. Examine the impact of 73rd Constitutional Amendment on the nature and role of Panchayati Raj Institutions in India. 20

5. "Independence of judiciary, a necessary condition for ensuring responsive government, cannot be overplayed." Comment. 20
 6. Elaborate some of the green initiatives undertaken in India. 20
 7. Discuss the various reforms pertaining to better law and administration as recommended by the Second Administrative Reforms Commission in India in 2008. 20
 8. Explain the concept and modes of e-Learning. 20
 9. "Corporate responsibilities for the environment and local communities has gathered momentum in the form of corporate social responsibility." Discuss. 20
 10. "Self-help groups have become the vehicle of change for the poor and marginalised." Elucidate. 20
-

लोक प्रशासन में पी.एच.डी.
(पी.एच.डी.पी.ए.)

सत्रांत परीक्षा

जून, 2019

आर.पी.ए.-103 : शासन में समकालीन मुद्दे

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

(कुल का : 70%)

नोट : निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए । सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।

1. नवीन लोक प्रबंधन की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और इसके सैद्धांतिक आधारों का उल्लेख कीजिए । 20
2. भारत में मातृ और बाल स्वास्थ्य के कुपोषण से संबंधित मुद्दों का परीक्षण कीजिए । 20
3. “डिजिटल भारत, अंतिम छोर तक की समावेशिता को संभव बनाता है ।” टिप्पणी कीजिए । 20
4. भारत में पंचायती राज संस्थाओं के स्वरूप और भूमिका पर 73वें सांविधानिक संशोधन के प्रभाव का परीक्षण कीजिए । 20

5. “अनुक्रियाशील सरकार सुनिश्चित करने की अनिवार्य शर्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, परन्तु न्यायपालिका की इस भूमिका को हम आवश्यकता से अधिक तूल नहीं दे सकते।” टिप्पणी कीजिए। 20
6. भारत में किए गए कुछ हरित प्रयासों की सविस्तार व्याख्या कीजिए। 20
7. वर्ष 2008 में भारत में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा संस्तुत बेहतर कानून और प्रशासन से संबंधित विभिन्न सुधारों की चर्चा कीजिए। 20
8. ई-अधिगम की अवधारणा और तरीकों की व्याख्या कीजिए। 20
9. “पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के लिए कॉर्पोरेट उत्तरदायित्वों ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में संवेग प्राप्त किया है।” चर्चा कीजिए। 20
10. “स्व-सहायता समूह गरीब तथा हाशिए के लोगों के लिए परिवर्तन का वाहक बन गए हैं।” व्याख्या कीजिए। 20